म.प्र. में सेमेस्टर पद्धति – एक मूल्यांकन

डॉ. साधना झांझरी*
***श्री क्लॉथ मार्केट कन्या वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर**

शोध सारांश

विश्व–विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से वार्षिक पाठ्यक्रम की जगह सेमेस्टर पद्धति को अपनाने के लिये दबाब बनाया । फलस्वरूप म.प्र. में 2008–09 से प्रदेश के सभी विश्व–विद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई । इस प्रणाली को लागू करने के साथ ही यह आवश्यक था की महाविद्यालयों और विश्व–विद्यालयों में पर्याप्त स्टॉफ और संसाधनों में वृद्धि की जाये, जो की नहीं हुआ । सेमेस्टर से सभी के कार्य भार में वृद्धि हुई, परिणाम यह हुआ कि सेमेस्टर लागू होने के बाद से एक भी वर्ष न तो समय पर परीक्षा हुई और न ही परिणाम घोषित हुए। वर्ष भर स्टॉफ परीक्षा संचालन में ही लगा रहा, अध्यापन कार्य प्रभावित होता रहा, जिन उम्मीदों से यह प्रणाली चालू की गई थी उसकी पूर्ति नहीं हो पायी । यदि इस प्रणाली को सफल बनाना है तो , पाठ्यक्रम में परिवर्तन , परीक्षा व्यवस्था में सुधार , पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाना होंगे, अन्यथा इस प्रणाली को समाप्त कर वार्षिक परीक्षा प्रणाली को ही पुनः लागू करके ही शिक्षा व्यवस्था को पुनः सुधारा जा सकता है।

कुंजीशब्दः सेमेस्टर पद्धति, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, अध्यापन ,पाठ्यक्रम ।

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा प्रणाली का केन्द्र बिन्दु परीक्षा रही है । अर्थात सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली परीक्षा पद्धति के इर्दगिर्द होती है । क्या पढ़ाना है? कितना पढ़ाना है? कैसे पढ़ाना है? इन सब प्रश्नों का उत्तर केवल परीक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। अतः एक सर्वसम्मत राय यह बनती है की यदि शिक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हो तो परीक्षा प्रणाली को सुधारना पर्याप्त होगा । गत दस वर्षों में परीक्षा पद्धति में तेजी से परिवर्तन हुए। वर्ष 2008–09 से म.प्र. में प्रथम बार वार्षिक परीक्षा पद्धति के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई।

शोध के उद्देश्य

सेमेस्टर प्रणाली का अध्ययन करना।

सेमेस्टर प्रणाली किन उम्मीदों से लागू की गई थी इसका अध्ययन करना ।

यह पद्धति कितनी सफल हो पायी और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

शोध प्रविधि

अध्यापन व परीक्षा कार्य से सम्बन्धित रहने के कारण प्रस्तुत शोध आलेख निरिक्षण पद्धति पर आधारित है ।

सेमेस्टर प्रणाली – एक परिचय

वार्षिक परीक्षा पद्धति में स्नातक स्तर पर 9 प्रश्न पत्र होते थे । विद्यार्थियों को 10 में से 5 प्रश्न हल करने होते थे। जिसमें प्रत्येक इकाई में आतंरिक विकल्प होता था। समयावधि तीन घंटे होती थी। वर्ष 2008–09 से लागू सेमेस्टर प्रणाली में वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित होने लगी । इसमें भी प्रश्न पत्रों को संख्या 9 रखी गई। वार्षिक पद्धति वाले पाठ्यक्रम को ही दो भागों में विभाजित कर दिया गया । प्रश्न पत्र के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे निम्न तीन भागों में विभाजित कर दिया गया :-

1 – वस्तुनिष्ठ प्रश्न

2 – लघु उत्तरीय प्रश्न

3 – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसित 12 विधाओं में से चयन कर प्रत्येक सेमेस्टर में दो सी.सी.ई. जो महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है ।छात्राओं को यह परीक्षा भी देनी होती थी जिसके 15 अंक निर्धारित थे। सी.सी.ई. का मुख्य उद्देश्य उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण करने के साथ ही साथ विद्यार्थी उन 12 विद्याओं से सम्बन्धित कौशल हासिल कर सके। इसके साथ ही प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को रोजगार के सम्बन्ध में एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता था तथा अंतिम सेमेस्टर विद्यार्थियों को दो माह का रोजगार भी प्राप्त करना होता था। वर्ष 2011–12 में पुनः परीक्षा पद्धति में परिवर्तन किया गया । अब 9 प्रश्न पत्रों के स्थान पर 5 प्रश्न पत्र हो गये अर्थात जो पहले 9 पेपर में कोर्स को आधा आधा किया गया था अब 9 पेपर को दो सेमेस्टर में विभाजित कर दिए गये। परिवर्तन केवल इतना हुआ कि सेमेस्टर पद्धति में परिवर्तन किया गया। प्रोजेक्ट अब केवल अंतिम सेमेस्टर ही विद्यार्थियों को तैयार करना है। सी.सी.ई. दो के स्थान पर एक कर दिए गये।

सेमेस्टर प्रणाली – एक उम्मीद

विश्व–विद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुदान प्राप्त विष्वविद्यालयों के ऊपर दबाव बनाया गया कि वह अपने यह वार्षिक पाठ्यक्रम/परीक्षा की जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू करे। प्रदेश में वर्षों से शिक्षा की जो बदहाली जारी थी उससे निजात पाने के लिए सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने तुरंत सेमेस्टर प्रणाली का खाका तैयार कर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सहमति दर्ज करवा कर 2008 में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इसे लागू करवा दिया गया। सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के पीछे शिक्षा विदों का यह तर्क रहा की विद्यार्थियों पर पढाई का बोझ कम होगा, पढाई का नियोजन ज्यादा अच्छी तरह से कर पायेंगे , सी.सी.ई. की विभिन्न विधाओं से उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होगा, प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी स्नातक स्तर पर ही रोजगार की बारीकियों को समझ पायेंगे और डिग्री प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थी में इतना कौशल विकास हो जायेगा कि वह आसानी से रोजगार प्राप्त कर लगा । प्रारम्भ में विद्यार्थियों को भी यह प्रणाली अपने हित में लगी, उन्हें लगा की कोर्स दो भागों में बट जायेगा साथ ही साथ एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में उन्हें अपना मूल्यांकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जायेगा। 2011 में दिल्ली विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो दिनेश सिंह के अनुसार इस सिस्टम से छात्रों में पढाई के प्रति विशेष रूचि जागृत होगी, छोटे–छोटे सिलेबस के हिसाब से पढाई करने का लाभ मिलेगा और छात्रों का पढाई के प्रति अनुशासन बढेगा । जिसका लाभ उनके जीवन में बेहतर भविष्य बनाने में मिलेगा।

प्रदेश में सभी पाठ्यक्रम में सेमस्टर पद्धति लागू हुए 8 वर्ष हो चुके है। आवश्यकता है कि इस पद्धति का मूल्यांकन किया जाय , जिन उम्मीदों के तहत यह पद्धति लागू की गई थी क्या वह उम्मीदें पूरी हो पायी है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार

हुआ है। छात्रों का पढाई के प्रति रुझान बड़ा है? क्या यह पद्धति देश को एक अच्छा नागरिक दे पा रही है? ऐसे कई सवाल उत्पन्न होते है। वास्तव में जब गम्भीरता से इस पर विचार किया गया, आपसी सलाह मशवरा किया, छात्रों से चर्चा की गई तो निष्कर्ष अनुकूल नहीं पाये गये । दरअसल म.प्र. सरकार में सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने से पहले उच्च शिक्षा का कोई आकलन नहीं किया, आज उच्च शिक्षा संस्थान बदहाली के जिस मुकाम पर पहुंचे है यह अचानक घटी घटना नहीं है, बल्कि लम्बी प्रक्रिया का नतीजा है, जिसमे सेमेस्टर प्रणाली ने आग में घी की तरह काम किया। इस प्रणाली के समक्ष प्रमुख समस्याएं इस तरह रही :

- कॉलेज व यूनिवर्सिटी में आवश्यक स्टॉफ सहित अन्य सुविधाओं का अभाव रहा ।
- प्रदेश में इस प्रणाली में न तो परीक्षा समय पर हुई और न ही रिजल्ट समय पर आया। रिजल्ट आने के पहले ही अगले सेमेस्टर परीक्षा की तारीख आ जाती है।
- वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित होने से विद्यार्थियों को दो बार फीस जमा करवाना, दो बार फॉर्म भरना, ए.टी.के.टी. हो तो उसकी अलग फीस, फॉर्म भरना, वर्ष में दो बार सी.सी.ई. देना, दो बार पुस्तकों की व्यवस्था करना, सही मायने में विद्यार्थी इन्हीं सब कारवाही में उलझकर रह जाता है। परीक्षा परिणाम से संतुष्टि न हो तो उसकी कारवाही अलग करनी होती है।
- सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से विद्यार्थियों की सांस्कृतिक कार्यक्रम , एन. सी. सी., एन. एस. एस. जैसी गतिविधियाँ लगभग ठप हो गई है।
- इस सिस्टम से छात्रों पर कई बंदिशे लागू हो गई इससे छात्र राजनीति व अन्य सामाजिक गतिविधियों से दूर होते गये ।
- परीक्षा कार्यक्रम सभी सेमेस्टर के लिये एक साथ नहीं होने से लगभग हर एक दो माह के बाद महाविद्यालय में परीक्षा संचालित करनी होती है, इससे अध्ययन–अध्यापन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पता।
- सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों के निरन्तर मूल्यांकन के लिए असाइनमेंट दिए जाते है, लगातार टेस्ट होते हैएसेमेस्टर प्रणाली में छात्रों के निरन्तर मूल्यांकन के लिए असाइन्मेंट दिये जाते है, लगातार टेस्ट होते है, प्रोजेक्ट तैयार करवाये जाते है , जिनके अंक परीक्षा परिणाम में जोडे जाते है , लेकिन अधिकांश महाविद्यालयों में यह व्यवस्था ही ध्वस्त है, कई जगह टेस्ट लिये बिना ही यूनिवर्सिटी को अंक भेज दिए जाते है, प्रेक्टिकल एग्जाम में भी यही होता है, इससे शिक्षा का स्तर सुधरने के बजाय गिरता जा रहा है ।
- प्राध्यापकों के सामने कभी चुनाव तो कभी सिंहस्थ मेले की तैयारियों के कारण कोर्स को समय से पहले पूरा करने की चुनौती बनी रहती है।
- जिन महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएँ नहीं लगती वह सेमेस्टर प्रणाली ,आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट वर्क जैसी आदर्श व्यवस्था केवल खानापूर्ति बन कर रह गई।
- वार्षिक परीक्षा प्रणाली में भी छात्रों का मुख्य उद्देश्य परिक्षाओं में अधिक से अधिक नम्बर हासिल करना था,सेमेस्टर प्रणाली ने इस मानसिकता को और खाद –पानी दिया है। अध्ययन से यह बात सामने आई कि सेमेस्टर पद्धति लागु होने के बाद से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के प्रतिशतों में बहुत अधिक वृद्धि हुई ,जबकि वार्षिक परीक्षा की तुलना में बौद्धिक स्तर में गिरावट आई है।

- सेमेस्टर पद्धति में पाठ्यक्रम का जोड– तोड कर जो निर्धारण किया गया उससे विद्यार्थी विषय की गहनता से वंचित होते जा रहे है ,इसके साथ ही पेपर का पेटर्न (आब्जेक्टिव ,लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)इस तरह निर्धारित है कि छात्र विषय का सतही अध्ययन करके पर्याप्त अंक हासिल कर सकते है। कुल मिलाकर पूरी व्यवस्था सेमेस्टर में गई कि विद्यार्थियों को पास होने के लिए नहीं बल्कि फेल होने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

शिक्षा के स्तर में सुधार व उसे रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई ,लेकिन जितनी आशा की गई थी उतनी सफल यह पद्धति नहीं हो पाई। उपरोक्त समस्यायों पर चिन्तन करने के उपरान्त यह मत बनता है कि यह पद्धति केवल उन कोर्सेस में उपयोगी हो सकती है विद्यार्थियों की संख्या कम हों ,छात्र शिक्षक अनुपात उचित हो तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। परम्परागत कोर्सेस में यह पद्धति सफल नहीं पाई है ,अतः आवश्यक है कि वहां पुनः आवश्यक परिवर्तन के साथ वार्षिक पद्धति को लागू किया जाय। पाठ्यक्रम में वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किया जाय ,आंतरिक मूल्यांकन को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है ,अंतिम वर्ष में एक या दो माह का रोजगार प्रशिक्षण दिया जाय ,यह प्रशिक्षण केवल उन छात्रों के लिए हो स्वेच्छा से लेना चाहते है, बाकि छात्रों के लिये एक थ्योरी पेपर जो रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो,ऐसा कोर्स डिजाईन कर पढाया जाना चाहिये। सत्र का केलेण्डर बनाया जाय और उसका सख्ती से पालन किया जाय ,इससे विद्यार्थियों को पढाई के साथ –साथ अन्य गतिविधियों में जैसे एन.एस.एस., एन.सी.सी. ,युवा उत्सव तथा अन्य महाविद्यालयीन स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा इससे उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। वार्षिक पद्धति लागू करने से छात्रों को अध्ययन – अध्यापन हेतु पर्याप्त समय मिलेगा, पर्याप्त समय होने के कारण विषय का गहनता से अध्ययन किया जा सकता है। परम्परागत कोर्सेस में वार्षिक पद्धति लागू करने से विद्यार्थियों को अपने पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो पाएगा ताकि स्नातक होने के बाद वह नौकरी ढूंढने के बजाय पूर्ण रूप से अपने परिवार के व्यवसाय को संचालित कर सके। वार्षिक पद्धति को लागू करने से विश्वविद्यालयों के कार्य भर में भी होगी और वे समय पर परीक्षा संचालन व परिणाम घोषित कर पाएंगे। इसका लाभ विद्यार्थियों को भी होगा की वे आगे विभिन्न कोर्सेस में प्रवेश के सम्बन्ध में प्लानिंग कर पायेँगे। वार्षिक परीक्षा पद्धति लागू करने से विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार पुस्तकें क्रय करना होगी, एक बार परीक्षा फॉर्म व फीस जमा करना होगी, एक बार परीक्षा होने से स्टेशनरी की बचत होगी, सबसे अधिक मूल्यवान समय की बचत होगी और बचाए गए समय को प्राध्यापक अध्यापन कार्य में व विद्यार्थी अध्ययन में लगा सकेंगे। बिना स्टाफ और संसाधनों के कोई भी सिस्टम सफल नहीं हो सकता, अतः आवश्यक है कि या तो संसाधन बढाये जाय या फिर पुनः वार्षिक पद्धति को लागू कर बिगडे हुए शैक्षणिक सत्र को पुनः व्यवस्थित किया जाय इसी में विद्यार्थियों का हित समाहित है ।

संदर्भ सूची

- महेश शर्मा, 11 मार्च 2012, सेमेस्टर प्रणाली: पढाई नदारद, परीक्षा पर जोर, http://aajtak-intoday-in/story/semester&system&in&mps&colleges&destroy&education&system&1&693276-html

- राकेश कुमार, 24 जून 2009 सेमेस्टर प्रणाली से कितना होगा छात्रों का हित?, http://www-jagranjosh-com/articles
- डॉ हेमा मिश्रा, 'वाणिज्य शिक्षा के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण'लघु शोध प्रबन्ध – यू.जी.सी. से वित्त पोषित